



- 21 वर्षों के अन्तराल में रेस्पोंड क्रम-1 द्वारा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं कराना सन्देशास्पद है। वर्तमान में जमीनों की कीमत बढ़ जाने से रेस्पोंड क्रम-1 ने जमीन के बारे में अवैधानिक रूप से विवाद किया है। इस बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर जेरअपील निर्णय/आदेश पारित करने में त्रुटि की है। नामा0 सं0 415 के विरुद्ध अपील लगभग 6 वर्ष बाद पेश की गई थी जो अवधि बाधित थी अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दू पर गौर किये बिना निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी का निर्णय दिनांक 17.1.2019 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।
- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंड को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत अपील प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।
- 3 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि ग्राम पंचायत द्वारा फौती नामान्तरकरण सं0 415 मृतक खातेदार राजेन्द्रसिंह के प्राकृतिक वारिसान पुत्र पुत्री पत्नी के नाम तस्दीक किया है इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। यदि रेस्पोंड उक्त आराजी में कोई हक एवं अधिकार रखते हैं तो उन्हें सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिये। रेस्पोंड क्रम-1 के टाईटल का बिन्दू नामान्तरकरण की कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता। हितबद्ध पक्षकार हैं या नहीं यह बिन्दू नियमित वाद की कार्यवाही तय हो सकता है। बहस में यह भी प्रकट किया कि भागीदारी समाप्ती और पार्टनरशीप डीड में हस्ताक्षर अलग-2 है। फौती नामा0 सं0 415 तस्दीक किया गया था उसमें कोई गलती नहीं थी। पार्टनरशीप डीड के आधार पर तहसीलदार क्या तय करेगा। रेस्पोंड को कोई आपत्ति है तो सक्षम न्यायालय में दावा करना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने 6 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दू पर निर्णय पारित किये बिना ही स्वीकार करने में त्रुटि की है अन्त में आरआरटी 2018(2) पेज 1344 आरआरटी 2017(2) पेज 1356 आरआरटी 2012(1) पेज 374 आरआरडी 1988 पेज 311 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।
- 4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट क्रम-1 ने बहस में प्रकट किया कि अपीलांट के पिता की फर्म सलूजा एन्टरप्राइजेज के पार्टनर के मामले में दिनांक 1.4.96 को भागीदारी समाप्त होकर अलग हो जाने से प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का अब कोई हक व अधिकार नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में अपील आधारहीन होने से खारिज योग्य है।
- 5 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोंड क्रम-1 अभिभाषक सुनी जाकर बहस पर मनन किया तथा प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का भली-भाँति अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध आधार के अवलोकन से विवादित आराजी का नामा0 सं0 415 दिनांक 20.12.11 को ग्राम पंचायत हीरियाखेडी द्वारा इन्टर प्राइजेज पार्टनरशीप फर्म जरिये पार्टनर राजेन्द्रसिंह सलूजा पुत्र ज्ञानसिंह जाति पंजाबी के फौत होने के बाद राजेन्द्रसिंह के स्थान पर उसके वारिसान के नाम दर्ज किया गया था जिसे अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नामा0 आदेश पारित करने से पूर्व फर्म के पक्ष को नहीं सुने जाने तथा फर्म की भूमि पर मृतक राजेन्द्रसिंह का एक्सोल्यूट राईट प्राप्त नहीं होने से ग्राम पंचायत द्वारा नामा0 सं0 415 दिनांक 20.12.2011 दिया गया आदेश नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के विपरीत होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को वादग्रस्त भूमि के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर तथा उन्हें साक्ष्य आदि का सम्यक अवसर देकर

पुनः नवीन सिरें से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया गया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण में अपीलांत का मुख्य तर्क है कि इन्टर प्राईजेज पार्टनरशीप फर्म जरिये पार्टनर राजेन्द्रसिंह सलूजा का फौती नामा० उसके वारिसान पुत्र पुत्री पत्नी के नाम तस्दीक किया गया था जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। फर्म से भागीदारी समाप्ति और पार्टनरशीप डीड में हस्ताक्षर अलग-2 है। रेस्प० क्रम-1 के टाईटल का बिन्दू नामान्तरकरण की कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता। हितबद्ध पक्षकार है या नहीं यह बिन्दू नियमित वाद की कार्यवाही तय हो सकता है। इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्प० क्रम-1 का तर्क है कि फर्म से राजेन्द्रसिंह सलूजा की भागीदारी समाप्त होकर अलग हो जाने से अपीलांत का वादग्रस्त आराजी से कोई सरोकार नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। उपरोक्त तथ्यों एवं तर्कों के अवलोकन उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नामा० सं० 415 दिनांक 20.12.2011 पारित करने से पूर्व फर्म के पक्ष को नहीं सुने जाने तथा फर्म की भूमि पर मृतक राजेन्द्रसिंह का एक्सोल्यूट राईट प्राप्त नहीं होने व आदेश नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के विपरीत होने से अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें सभी पक्षों को पुनः सुनवाई व अपने साक्ष्य सबूत रखने का अवसर भी दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुकूल है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत अपील प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरटी 2018 (2) पेज 1344, आरआरटी 2017 (2) पेज 1356, आरआरटी 2012 (1) पेज 374, आरआरडी 1988 पेज 311 चस्पा नहीं होते हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय का उक्त निर्णय न्यायोचित होने से इस न्यायालय को किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता/गुजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांत सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

( अनुरम भार्गव )  
अति० सभागीय आयुक्त  
कोटा